

खोले के हनुमानजी मंदिर परिसर में 436 मीटर लंबा स्वचालित रोप-वे बनेगा

24 टॉली वाला यह रोप-वे एक घंटे में 800 यात्रियों को सफर करवा सकेगा

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजधानी जयपुर में खोले के हनुमानजी मंदिर परिसर में खोले का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोप-वे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अन्रूपमा माता मंदिर से खोले के हनुमानजी मंदिर को पहाड़ी स्थित वैष्णोमाता मंदिर तक 436 मीटर लंबा रोप-वे बनाया जा रहा है। 24 टॉली वाला यह रोप-वे एक घंटे में 800 यात्रियों को सफर करवा सकेगा। कलेक्टर ने इसका निर्माण कार्य दो साल में पूरा करने को कहा है।

शुक्रवार को जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने खोले के हनुमान मंदिर परिसर में पहुंचकर रोप-वे निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस रोप-वे का नाम अन्रूपमा माता रोप-वे होगा, जो कि प्रदेश का पांचवां और जयपुर जिले का सामोद हनुमानजी रोप-वे के बाद दूसरा रोप-वे होगा।

अन्रूपमा माता मंदिर से खोले के हनुमानजी मंदिर को पहाड़ी स्थित वैष्णोमाता मंदिर तक 436 मीटर लंबा रोप-वे बनाया जा रहा है। जो कि जयपुर का सबसे बड़ा रोप-वे होगा। इसके निर्माण के लिए फर्म और जयपुर जिला प्रशासन के बीच करार हुआ है, जिसके बाद फर्म को रोप-वे अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान रोप वे निर्माण की फर्म के पदाधिकारियों ने कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को बताया कि पांच टावरों पर संचालित किए जाने वाले रोप



जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने शुक्रवार को खोले के हनुमान मंदिर परिसर में पहुंचकर रोप-वे निर्माण का निरीक्षण किया।

वे की ऊंचाई 85 मीटर होगी। 24 टॉली वाले इस रोप-वे की क्षमता 800 यात्री प्रति घंटा होगी। कलेक्टर ने निर्माता फर्म को 2 साल में रोप-वे निर्माण के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए रोप-वे निर्माण में गुणवत्ता का खास ध्यान दिया जाए। निर्माण के दौरान और संचालन के शुरू होने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से रोप-वे के सुरक्षा मापदंडों की नियमित रूप से जांच की जाएगी। रोप-वे के निर्माण में जयपुर की विरासत, शिल्पकला और

वैभव को छटा देखने को मिलेगी। कलेक्टर ने कहा कि रोप-वे निर्माण करने वाली फर्म को 0 से 5 आयुर्वर्ष वाले बच्चों और 70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के साथ-साथ दिव्यांगों को रोप-वे के जरिये निःशुल्क सफर करवाने के लिए निर्दिष्ट किया

जाएगा। रोप-वे की एक तरफ का सफर करीब साढ़े 4 मिनट में पूरा होगा। इस दौरान यात्रियों को जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाने के लिए टॉली को बीच सफर में दो बार रोका जाएगा। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दक्षिण मोहम्मद अब्दुल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ रोप वे निरीक्षक सुरेन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अजय भूषेण सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

- कलेक्टर ने 2 साल में इसे शुरू करने को कहा
- अन्रूपमा माता के नाम पर बन रहे इस रोप-वे में बच्चों, दिव्यांगों और बुजुर्गों को निःशुल्क सफर कराया जायेगा
- रोप-वे से एक तरफ का सफर करीब साढ़े 4 मिनट में पूरा होगा, यात्रियों को जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाने के लिए टॉली को बीच सफर में दो बार रोका जाएगा

वैभव को छटा देखने को मिलेगी। कलेक्टर ने कहा कि रोप-वे निर्माण करने वाली फर्म को 0 से 5 आयुर्वर्ष वाले बच्चों और 70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के साथ-साथ दिव्यांगों को रोप-वे के जरिये निःशुल्क सफर करवाने के लिए निर्दिष्ट किया

प्रदेश भाजपा में जिलाध्यक्षों का बदलाव अब उपचुनाव के बाद ही सम्भव होगा

जयपुर। प्रदेश भाजपा में पिछले कई महीनों से निष्क्रिय पड़े जिलाध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों का बदलाव अब उपचुनाव के बाद ही सम्भव होगा। पिछले दिनों हुई भाजपा की कोर कमिटी की बैठक में भाजपा के कोर ग्रुप के नेताओं ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए जिलाध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों के बदलाव पर चर्चा की थी।

वहीं इस पर भाजपा संगठन ने नए पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के लिए नए नाम भी तैयार किए हैं लेकिन सरदार शहर उपचुनाव, गुजरात चुनाव और जन आक्रोश यात्रा के शुरूआत होने के कारण इन नियुक्तियों में देरी हो रही है। इन नामों पर भाजपा संगठन के नेताओं ने इन नए नामों पर चर्चा होने के बाद ही बदलाव किया जाएगा। ऐसे में करीब आधा दर्जन जिलाध्यक्षों का बदलाव के लिए अब और इंतजार करना पड़ेगा। इस फेरबदल का आधार इन जिलों के पार्टी जिलाध्यक्षों की लचर परफॉर्मेंस को माना गया। अंदरखाने में चर्चा है कि पार्टी की राज्य इकाई से लेकर केंद्रीय संगठन की ओर से दिए जाने वाले अभियानों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले जिलाध्यक्षों पर गाज गिरने जा रही है। राजस्थान में वैसे तो 33 जिले हैं लेकिन भाजपा संगठन के लिहाज से कई जिलों में दो-दो जिलाध्यक्ष होने से इनकी संख्या 40 से भी ज्यादा है। चर्चा है कि दौसा, सर्वाइमाधोपुर, भरतपुर, बाड़मेर, उदयपुर, अजमेर सहित कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाने की तैयारी चल रही है। संगठनात्मक ढांचे में मजबूती को आगामी विधानसभा चुनाव में इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के अलावा भाजपा को कई नए तीसरे दलों की चुनौती का भी सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि आम पार्टी और कई तीसरे दल राजस्थान में अबकी चुनाव में भाग्य आजमाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आमजन में भाजपा की पैठ बनाने और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने के लिए जिलों के संगठन की बागडोर में बदलाव किए जाने की तैयारी की जा रही है। जिलाध्यक्षों का बदलाव नवंबर माह की शुरूआत में होना था लेकिन अब उपचुनाव, गुजरात चुनाव और जन आक्रोश यात्रा के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई है।

जिलाध्यक्ष के बदलाव को खबरों के बीच इशारे के लिए योग्य एवं ऊजवान चेहरों की तलाश किए हो गई हैं। हाल ही में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अलग-अलग जिलों के दौरो के दौरान बकायदा जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल होने जाने वाले संबंधित जिलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी जबरदस्त सक्रियता दिखाई। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी प्रदेश संगठन भी नए जिलाध्यक्षों के खय में सभी पक्षों का ख्याल रखते हुए अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले व्यक्ति के चयन को प्राथमिकता देना चाहता है।

प्रदेश की अदालतों में आज भी नहीं हुआ काम

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र नायगुण जोशी और संघर्ष समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल चौधरी सहित अन्य कर्मचारी नेताओं से वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद कर्मचारियों ने मांगी पूरी नहीं होने तक सामूहिक अवकाश जारी रखने का निर्णय लिया है। कर्मचारी मामलों की सीबीआई जांच, न्यायिक अफसर को एपीओ करने, मूलक के परिजनों को पचास लाख रुपये मुआवजा सहित एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र नायगुण जोशी और संघर्ष समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल चौधरी सहित अन्य कर्मचारी नेताओं से वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद कर्मचारियों ने मांगी पूरी नहीं होने तक सामूहिक अवकाश जारी रखने का निर्णय लिया है। कर्मचारी मामलों की सीबीआई जांच, न्यायिक अफसर को एपीओ करने, मूलक के परिजनों को पचास लाख रुपये मुआवजा सहित एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में परस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए जमाने की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

पुलिस अफसरों ने की राँक क्लाइम्बिंग



जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी में कांस्टेबल दीक्षांत परेड के बाद राजस्थान पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों व कांस्टेबलों द्वारा किए गए राँक क्लाइम्बिंग का पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने अवलोकन किया। अतिरिक्त महानिदेशक एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अकादमी में नियमित एवं अत्याधुनिक प्रशिक्षण के साथ ही पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को एडवेंचर गतिविधियों से भी रूबरू करवाया जा रहा है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सर्वश्री डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। राज्यभर में खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य से स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन कर श्रमिकों में अवेयरनेस, खनन सुरक्षा सप्ताहों के उपयोग के प्रति प्रेरित करने, मास्क आदि आवश्यक किट का वितरण और सिलिकोसिस जैसी बीमारी के लक्षण दिखने पर विलीय सहायता व ईलाज की व्यवस्था करवाई जा रही है।

एसीएस माईस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने गत 18 नवंबर को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में फोल्ड अधिकारियों को प्रदेश में खनन सुरक्षा व स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए थे।

जयपुर (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य सचिव माईस, पेट्रोलीयम व जलदाय डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। राज्यभर में खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य से स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन कर श्रमिकों में अवेयरनेस, खनन सुरक्षा सप्ताहों के उपयोग के प्रति प्रेरित करने, मास्क आदि आवश्यक किट का वितरण और सिलिकोसिस जैसी बीमारी के लक्षण दिखने पर विलीय सहायता व ईलाज की व्यवस्था करवाई जा रही है।

एसीएस माईस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने गत 18 नवंबर को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में फोल्ड अधिकारियों को प्रदेश में खनन सुरक्षा व स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए थे।

जयपुर (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य सचिव माईस, पेट्रोलीयम व जलदाय डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। राज्यभर में खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य से स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन कर श्रमिकों में अवेयरनेस, खनन सुरक्षा सप्ताहों के उपयोग के प्रति प्रेरित करने, मास्क आदि आवश्यक किट का वितरण और सिलिकोसिस जैसी बीमारी के लक्षण दिखने पर विलीय सहायता व ईलाज की व्यवस्था करवाई जा रही है।

एसीएस माईस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने गत 18 नवंबर को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में फोल्ड अधिकारियों को प्रदेश में खनन सुरक्षा व स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए थे।

एसीएस माईस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने गत 18 नवंबर को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में फोल्ड अधिकारियों को प्रदेश में खनन सुरक्षा व स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए थे।

आईएस अरोड़ा को अवमानना नोटिस जारी

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद एसीबी की ओर से भेजे 17ए की अनुमति का पत्र तय अवधि में निस्तारण नहीं करने पर प्रमुख आईटी सचिव अखिल अरोड़ा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस एएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवाणी की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अमेंट करणन की अवमानना याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा और अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि राजकोमिप इन्फो सर्विसेज लि. की ओर से 240 करोड़ रुपये की

जयपुर डेयरी को आरटीआई के दायरे में मानने के आदेश पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के गत 17 अगस्त के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत आयोग ने जयपुर डेयरी को आरटीआई के दायरे में मानते हुए सूचना मुहैया कराने को कहा था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में सूचना आयोग, पशुपालन सचिव और आरसीडीएफ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश जारीपु जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि. की याचिका पर दिए। अधिवक्ता डॉ. अनिल शर्मा ने अदालत को बताया कि

राज्य सूचना आयोग ने गत 17 अगस्त को याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए मांगी गई सूचना मुहैया कराने को कहा था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहकारी संस्था है और वह किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है। जयपुर डेयरी निजी

राज्य सूचना आयोग ने गत 17 अगस्त को याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए मांगी गई सूचना मुहैया कराने को कहा था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहकारी संस्था है और वह किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है। जयपुर डेयरी निजी

राज्य सूचना आयोग ने गत 17 अगस्त को याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए मांगी गई सूचना मुहैया कराने को कहा था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहकारी संस्था है और वह किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है। जयपुर डेयरी निजी

राज्य सूचना आयोग ने गत 17 अगस्त को याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए मांगी गई सूचना मुहैया कराने को कहा था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहकारी संस्था है और वह किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है। जयपुर डेयरी निजी

राज्य सूचना आयोग ने गत 17 अगस्त को याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए मांगी गई सूचना मुहैया कराने को कहा था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहकारी संस्था है और वह किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है। जयपुर डेयरी निजी

राज्य सूचना आयोग ने गत 17 अगस्त को याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए मांगी गई सूचना मुहैया कराने को कहा था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहकारी संस्था है और वह किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है। जयपुर डेयरी निजी

राज्य सूचना आयोग ने गत 17 अगस्त को याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए मांगी गई सूचना मुहैया कराने को कहा था। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहकारी संस्था है और वह किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है। जयपुर डेयरी निजी

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम पुष्पा मेघरानी के स्थान पर पुष्पा देवी कर लिया है अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-55/126, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर

आवश्यकता
आयुर्वेदिक कंपनी शिक्षित बेरोजगार महिलाएं, पुरुष, लड़कियां, गृहणियां घर बैठे दवा पैकिंग करके 25000 से 60000/- कमाएं (एनओसी चार्ज- 2150/- संपर्क कर-8420229677

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेरे अभिभावक मोहन लाल पुत्र सर, श्री गंगाबा, तिलारी चण्डाली रोड का मालिक, यात्रा विभाग, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर का निवासी हूँ। मैंने अपने पिता का नाम पुष्पा देवी कर लिया है अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-55/126, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेरे अभिभावक मोहन लाल पुत्र सर, श्री गंगाबा, तिलारी चण्डाली रोड का मालिक, यात्रा विभाग, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर का निवासी हूँ। मैंने अपने पिता का नाम पुष्पा देवी कर लिया है अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-55/126, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेरे अभिभावक मोहन लाल पुत्र सर, श्री गंगाबा, तिलारी चण्डाली रोड का मालिक, यात्रा विभाग, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर का निवासी हूँ। मैंने अपने पिता का नाम पुष्पा देवी कर लिया है अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-55/126, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर

स्वोया पाया
मेरा आवास संख्या एफ-920 (ई) जेडीए कॉलोनी गोविन्दपुरा सांगानेर के मूल काजानत कहीं खो गए। मिलने पर सूचित करें। सफीक-मोबाइल 9950100528

स्वोया पाया
मेरा आवास संख्या एफ-920 (ई) जेडीए कॉलोनी गोविन्दपुरा सांगानेर के मूल काजानत कहीं खो गए। मिलने पर सूचित करें। सफीक-मोबाइल 9950100528

स्वोया पाया
मेरा आवास संख्या एफ-920 (ई) जेडीए कॉलोनी गोविन्दपुरा सांगानेर के मूल काजानत कहीं खो गए। मिलने पर सूचित करें। सफीक-मोबाइल 9950100528

स्वोया पाया
मेरा आवास संख्या एफ-920 (ई) जेडीए कॉलोनी गोविन्दपुरा सांगानेर के मूल काजानत कहीं खो गए। मिलने पर सूचित करें। सफीक-मोबाइल 9950100528

स्वोया पाया
मेरा आवास संख्या एफ-920 (ई) जेडीए कॉलोनी गोविन्दपुरा सांगानेर के मूल काजानत कहीं खो गए। मिलने पर सूचित करें। सफीक-मोबाइल 9950100528

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

